CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

जम्मू-कश्मीर सरकार 2.5 लाख किसानों को कृषि-कौशल में प्रशिक्षित करेगी

अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस), कृषि उत्पादन विभाग, अटल डुल्लू ने आज यहां सिविल सचिवालय में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में कौशल विकास की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में डॉ. मंगला राय एपेक्स कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशों पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में लगे 2.5 लाख किसानों को कौशल सुधार और उद्यमशीलता से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना है।

बैठक के दौरान, समग्र कृषि विकास कार्यक्रम पर एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें किसानों के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की रूपरेखा दी गई। कृषि और बागवानी में 21, कृषि इंजीनियरिंग में 3, वानिकी में 4, रेशम उत्पादन में 3, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान में 6, मत्स्य पालन में 2 और ग्रामीण व्यवसाय प्रबंधन में 1 सहित कुल 29 कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए थे।

पशुधन की नई नस्लों का पंजीकरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने मवेशी, भैंस, बकरी और सुअर सहित पशुधन प्रजातियों की 10 नई नस्लों को पंजीकृत किया है, जिससे स्वदेशी नस्लों की कुल संख्या 212 हो गई है।

10 नई नस्लों में मवेशियों की तीन नई नस्लें (कथानी, सांचोरी, मैसिलम), भैंस की एक नस्ल (पूर्णनाथदी), तीन बकरी की नस्लें (सोजत, करौली, गुजरी) और तीन सुअर की नस्लें (बांदा, मणिपुरी ब्लैक, वाक चंबिल) शामिल हैं।

आईसीएआर-राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, करनाल (एनबीएजीआर) देश की नस्लों के पंजीकरण के लिए नोडल एजेंसी है। देशी नस्लों की पहचान और पंजीकरण 2010 के बाद ही शुरू हुआ। वे नस्लें जो पंजीकृत या पहचानी नहीं हैं, उन्हें 'अवर्णित' कहा जाता है।

सरकार ने गोवंश की आवाजाही पर लगी रोक हटाई

गांठदार त्वचा रोग के लिए जम्मू और कश्मीर को "मुक्त क्षेत्र" घोषित करने के बाद, कृषि उत्पादन विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश के बाहर से कुलीन स्वस्थ डेयरी पशुओं के आयात के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर में गोवंश के अंतर जिला और अंतर जिला आंदोलन पर प्रतिबंध हटा दिया है।

इस संबंध में जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि पीसीआईसीडीए, अधिनियम 2009 में निहित "मुक्त क्षेत्र" से संबंधित सभी प्रावधानों का यूटी के बाहर से डेयरी पशुओं का आयात करते समय कड़ाई से पालन किया जाएगा।

यह बताया गया है कि यूटी और पड़ोसी राज्यों में भी यह बीमारी नियंत्रण में है। जुलाई 2022 से जम्मू-कश्मीर में लगभग 72728 मवेशी गांठदार त्वचा रोग से पीड़ित हैं, जिनमें से 3015 पशुओं की इस बीमारी के कारण मौत हो गई।

कृषि ऋण में किसानों की हिस्सेदारी क्षेत्र के लिए सकारात्मक संकेत है

भारत में लाखों किसान हर मौसम में बीज और उर्वरक जैसे इनपुट खरीदने के लिए बैंकों द्वारा सब्सिडी वाले अल्पकालिक, सस्ते फसल ऋण पर निर्भर हैं। सरकार तथाकथित सावधि ऋण भी प्रदान करती है, जो कि फसल ऋणों के विपरीत, विकास के लिए कृषि में पूंजी निवेश को महत्वपूर्ण बनाने के लिए लिया जाता है।

कुल कृषि ऋण में किसानों द्वारा लिए गए सावधि ऋणों की हिस्सेदारी - धन जो पूरी तरह से कृषि निवेश में जाता है - 2013-14 में 24.95% से बढ़कर 2021-22 में 41.51% हो गया है, जो चिंताजनक गिरावट की प्रवृत्ति को उलट रहा है।

2003-04 में, कुल कृषि ऋण में निवेश ऋण का हिस्सा 37% था, जो कि पिछली यूपीए सरकार के दौरान 2005-06 में 42% हो गया था। हालांकि, 2013-14 में यह 25% तक गिर गया।

"देश में कृषि ऋण प्रणाली के कामकाज" पर कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार पृष्ठभूमि नोट के नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 के दौरान कुल कृषि ऋण में निवेश ऋण का हिस्सा 41% था, एक प्रतिशत बिंदु 2006-06 में प्राप्त 42% के अपने चरम से नीचे।

खेती को सस्ता बनाने के लिए सरकार अल्पकालिक फसली ऋण पर सब्सिडी देती है। इसके अलावा, बैंकों को अनिवार्य रूप से किसानों को ऋण देना चाहिए क्योंकि कृषि एक "प्राथमिकता वाला ऋण देने वाला क्षेत्र" है। उदाहरण के लिए, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देना चाहिए।

उपभोक्ता ऋण की तुलना में किसानों को 7% सस्ता फसल ऋण मिलता है, जो 12% से 14% के बीच होता है। समय पर पुनर्भुगतान करने वालों के लिए, प्रभावी ब्याज दर 4% से भी कम है।

नई कृषि नीति 31 मार्च तक, धालीवाल कहते हैं

पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने नई कृषि नीति तैयार करने के लिए कृषि विशेषज्ञों की 11 सदस्यीय समिति का गठन किया है। धालीवाल ने कहा कि नई कृषि नीति 31 मार्च तक तैयार हो जाएगी।

धालीवाल ने कहा, पंजाब सरकार किसानों के कल्याण और राज्य की कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस मीटिंग में पंजाब के कोने-कोने से 2500 से अधिक प्रगतिशील किसान हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि इस बैठक के दौरान किसान कृषि नीति पर चर्चा करेंगे और उनके बहुमूल्य सुझाव लिए जाएंगे।

धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूजल, मिट्टी की सेहत और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नई कृषि नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

उन्होंने कहा कि नई कृषि नीति में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कृषि उपज के मूल्यांकन, निर्यात और कृषि विविधीकरण जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

धालीवाल ने कहा कि पंजाब एक पर्यावरण और स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है, जिसमें उपजाऊ भूमि अनुपजाऊ भूमि में बदल रही है। उन्होंने आगे कहा कि नई कृषि नीति के तहत नदियों के अतिरिक्त पानी को पंजाब के हर खेत तक पहुंचाने पर विचार किया जा रहा है।

दिसंबर 2022 में चारा महंगाई बढ़कर 28.66% हुई, दूध की ऊंची कीमतों से राहत के आसार नहीं

दूध की ऊंची कीमतों से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि चारे की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित चारा मुद्रास्फीति की वार्षिक दर दिसंबर 2022 में बढ़कर 28.66 प्रतिशत हो गई है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2022 में चारे का सूचकांक मूल्य 28.66 प्रतिशत बढ़कर 236.6 हो गया, जो एक साल पहले इसी महीने में 183.9 था।

दिसंबर 2022 में चारा मुद्रास्फीति 2021 के इसी महीने में 4.25 प्रतिशत की तुलना में अधिक थी। यह पिछले साल नवंबर में 27.66 प्रतिशत थी।

चारे की कीमतों में वृद्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे दूध उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, जो अंततः उपभोक्ताओं के घरेलू बजट को प्रभावित करती है। कैलेंडर वर्ष 2022 में अमूल और मदर डेयरी जैसे डेयरी ब्रांड ने अपने दूध के दाम कई बार बढ़ाए। इसके अलावा, चारे की बढ़ती कीमतों ने पशुपालन पर निर्भर परिवारों को भी नुकसान पहुंचाया है।

चारे की कीमतों में वृद्धि समग्र WPI मुद्रास्फीति में गिरावट के विपरीत है, जो दिसंबर 2022 में 4.95 प्रतिशत पर आ गई, जो नवंबर में 5.85 प्रतिशत थी। दिसंबर 2021 में यह 14.27 फीसदी रही।

एनडीडीबी, अमूल, नेफेड जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय सहकारी समिति के प्रवर्तकों में शामिल होंगे

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), अमूल और NAFED जैविक खाद्य उत्पादों के लिए नई घोषित राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति के पांच प्रवर्तकों में शामिल होंगे, जो उत्पादन, प्रमाणन और विपणन प्रणाली में सुधार करके किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

पिछले सप्ताह, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने जैविक उत्पादों, बीजों और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तीन नई राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी समितियों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

सूत्रों के अनुसार, गुजरात के आणंद में स्थित नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी की स्थापना 500 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ की जाएगी। सूत्रों ने कहा कि इसकी शुरुआती चुकता शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपये होगी।

एनडीडीबी, सहकारी नेफेड, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (जीसीएमएमएफ), जो अमूल ब्रांड के तहत दुग्ध उत्पादों का विपणन करता है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) इसके लिए आगे आए हैं। सूत्रों ने कहा कि इस नए समाज के प्रवर्तक बनेंगे और वे प्रारंभिक चुकता शेयर पूंजी के लिए 20-20 करोड़ रुपये का योगदान देंगे।

एनडीडीबी मुख्य प्रवर्तक होगा, उन्होंने कहा, इन उत्पादों को अमूल ब्रांड के तहत विपणन किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर उत्पादों के विपणन के लिए एक नए ब्रांड का भी अनावरण किया जाएगा।

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

ASCI
Agriculture Skill Council of India

CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

Milk Procurement Functionaries - Corporate Skill Development Program

Date: Jan 2023

Registration Open

Program Coverage

- Survey of Area & Village
- Organization of Milk Routes
- Organization of Milk Procurement Network
- Organization of Farmers Producer Institution
- Milk Collection / Testing & Record Keeping at Village Level
- Transportation & Logistics Management in Milk Procurement
- Milk Reception, Chilling & Quality Assessment at BMC / MCC
- BMC Operations
- Hiring & Placement of BMC/ MCC's
- Material Balancing at chilling centers
- Milk Pricing & Pricing system
- Communication, Media Development & Meeting Procedures
- Milk Productivity Enhancement Measures Viz. Animal Feeding, Breeding, Health Control
- Input Delivery
- Hygiene & Clean Milk Production
- Green-house gas Emission in Milk Production

Registration Charges:

Program	Physical Mode
Milk Procurement Functionaries - Corporate Skill Development Program (Residential Program)	Rs. 8,500/ - per candidate

Contact Details:

Anurag Kumar
CEDSI
Mob: 7972377422
Email: anurag@cedsi.in

CEDSI is Hiring !!!!!!!

हम कौन हैं?

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि कौशल परिषद (ASCI) के तत्वावधान में काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था "भारत में डेयरी कौशल के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CEDSI)", किसानों की आजीविका के सशक्तिकरण और बेहतरी में मदद करने के लिए, वेतनभोगी कर्मचारी, और डेयरी मूल्य श्रृंखला में अन्य हितधारक।

सीईडीएसआई सदस्यता उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं, विकास चिकित्सकों, डेयरी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और किसानों को डेयरी उद्योग के लिए आसन्न महत्व के मुद्दों पर बहस और चर्चा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगी।